भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4668

28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तमिलनाडु में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

4668. श्री जी. सेल्वम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य - केंद्रों (सीएचसी) की पर्याप्तता का आकलन किया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा मौजूदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सी एचसी) को उन्नत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) तमिलनाडु में सीएचसी में ऑपरेशन थियेटर, डायग्रोस्टिक सुविधाएं और इनपेशेंट वार्ड सहित चिकित्सा अवसंरचना की उपलब्धता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सीएचसी में चिकित्सा कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा भर्ती और तैनाती के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार की तमिलनाडु में मौजूदा सीएचसी को उप-जिला अस्पतालों में उन्नत करने की कोई योजना है;

(च) यदि हां, तो उन्नयन के लिए प्रस्तावित सीएचसी की संख्या क्या है तथा इसके उन्नयन की समय-सीमा क्या है; और

(छ) उन्नत सेवाओं और अवसंरचना सहित उन्नयन योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय होने के कारण, आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है, जिसमें उप-केंद्र, पीएचसी और सीएचसी जैसी नई स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों को स्थापित करने सहित, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में प्राप्त

प्रस्तावों के आधार पर उनके संसाधन दायरे में स्वास्थ्य मानव संसाधन (विशेषज्ञ डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता) की भर्ती के लिए सहायता भी शामिल है। आईपीएचएस 2022 के अनुसार सीएचसी के लिए जनसंख्या मानदंड मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 और पहाड़ी, आदिवासी या दुर्गम क्षेत्रों में 80,000 है, जबकि शहरी सीएचसी की अनुशंसा स्थानीय आवश्यकता, जो आमतौर पर जनसंख्या घनत्व और स्वास्थ्य सेवा पहुंच के आधार पर लगभग 2.5 लाख से 5 लाख की आबादी के लिए होता है, के आधार पर की जाती है। हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया 2022-23 के अनुसार तमिलनाडु राज्य सरकार में 483 सीएचसी है।

(ख): तमिलनाडु में सीएचसी में ऑपरेशन थियेटर, डायग्नोस्टिक सुविधाएं और इन-पेशेंट वार्ड सहित चिकित्सा अवसंरचना की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना की योजना बनाने, कार्यान्वयन और अनुरक्षण का दायित्व मुख्य रूप से राज्य का है। तमिलनाडु सहित राज्यों में चिकित्सा अवसंरचना का विवरण हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया 2022-23 में उपलब्ध है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है:-
https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

(ग) और (घ): तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकार मानव संसाधन यैक्तिकीकरण पर काम कर रही है।

(ङ) से (छ): भारत सरकार तमिलनाडु सहित पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा सुविधाकेंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए संगठित प्रयास कर रही है। जबकि सुविधाकेंद्रों को बेहतर बनाने का निर्णय राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सीएचसी की क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपना सहयोग देना जारी रखता है।

*****